	B.G.	M.G.	N.G
Locos			
Steam	..	4	207
Diesel	11	1	..
Electric	38	..	..
Coaches	1,184	1,339	569
Wagons	17,270	8,980	3,999
(in terms of 4—wheelers)			

(b) to (d) The overaged rolling stock is condemned when their condition so warrants and is disposed off by auction after taking away usable fittings and parts. The amount realised as a result of condemnation and auction of overaged stock normally varies from type to type also on condition basis.

बाण सागर तथा राजघाट परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि

335. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :**
श्रीमती रत्न कुमारी :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बाण सागर तथा राजघाट परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश की इस मांग पर केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) बाण सागर बांध परियोजना एक अंतर्राज्यिक बहुप्रयोजनी परियोजना है जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार 2 : 1: 1 के हिस्से के अनुपात में भागीदार राज्य हैं। सोन नदी पर 4 मिलियन एकड़ फुट सक्रिय संचयन क्षमता वाले एक बांध की योजना बनाई गई है जिसे भी 2 : 1 :1 के अनुपात में बांटा जाएगा। इसकी अनुमोदित लागत (1977 की दरों पर) 91.30 करोड़ रुपये है और नवीनतम अद्यतन की गई लागत (1982 की दरों पर) 260.5 करोड़ रुपए है। मार्च, 1983 तक बांध और आनुषंगिक निर्माण कार्यों पर हुआ व्यय 38.96 करोड़ रुपए है जिसमें से मध्य प्रदेश ने 20.11 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। 1983-84 के लिए निर्माण संबंधी कार्यक्रम के अनुसार 30 करोड़ रुपये की आवश्यकता की तुलना में राज्यों के बजट में 16 करोड़ रुपये की कुल धनराशि की व्यवस्था की गई है।

राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राज्यिक परियोजना है जिसमें उसकी लागत और लाभों में वे बराबर के हिस्सेदार हैं । मार्च, 1983 तक हुआ व्यय 43.40 करोड़ रुपये है जिसमें से मध्य प्रदेश ने 19.87 करोड़ रुपये का अंशदान किया है । 1983-84 के दौरान 30 करोड़ रुपये की प्रायोजित आवश्यकता की तुलना में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अपने-अपने बजटों में क्रमश: 7 करोड़ रुपये और 5.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 1983-84 के दौरान बाण सागर परियोजना के लिए 6 करोड़ रुपये (4 करोड़ रुपये बांध के लिए और 2 करोड़ रुपये नहरों के लिए) और राजघाट बांध परियोजना के लिए भी 6 करोड़ रुपये (5 करोड़ रुपय बांध के लिए और 1 करोड़ रुपये नहरों के लिए) की अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का अनुरोध किया है। इस मामले पर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

Supply of wheat, rice, kerosene etc. to Madhya Pradesh

336. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh have demanded an increase in the quota of wheat, rice, sugar, kerosene oil and cement during 1983;

(b) if so, what are the details thereof and whether the Central Government have accepted the demand; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) to (c) The Government of Madhya Pradesh have requested for increase in the allocations of wheat, rice, kerosene oil and cement during 1983, as under:—

Wheat: From the existing monthly allocation of 25,000 tonnes to 60,000 tonnes for public distribution system.

Rice: From the existing monthly allocation of 20,000 tonnes to 80,000 tonnes.

Kerosene: From the existing allocation of 18,600 tonnes for summer block (March to June, 1983) to 25,000 tonnes per month.

Cement: From the existing allocation of 1,06,300 tonnes to 4,50,000 tonnes per quarter.

Allocations of foodgrains from the Central Pool are made on a month to month basis taking into account the overall availability of stocks in the Central Pool, relative needs of the various States, market availability and other related factors. As a result of monthly reviews, the allocation are increased|decreased wherever necessary these allocation are only supplimental to the open market availability.

An extra ad hoc allocation of 3,000 tonnes of wheat for public distribution system was given to the State Government in March, 1983. Similarly, an extra ad hoc allocation of 5,000 tonnes of rice was given for the month of May, 1983.

As regards kerosene, the State Government have not furnished detailed justification for enhanced requirement. However, a quantity of 4,000 tonnes of kerosene was allotted to the State Government in the month of June, 1983, in addition to the monthly allocataion for making special arrangements for storing the same at suitable centres during the rainy season.

As regards cement, owing to limited availability of levy cement, it has not been possible to accede to the request of the State Government. However, in view of the expected increase in availability of cement during 1983-84 the monthly allocation to the Government of